



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

प्रयागराज, शुक्रवार 05 जून, 2020 ई०
(ज्येष्ठ 15, 1942 शक संवत्)

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा विभाग

[ऊर्जा (नि०नि०) प्रकोष्ठ]

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ

अधिसूचना संख्या उ०प्र०वि०नि०आ०/सचिव/नियमावली/2020-082

अधिसूचना

दिनांक 05 जून, 2020 ई०

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थकारी समस्त शक्तियों का प्रयोग करके पिछले प्रकाशन के बाद, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्वारा उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय वितरण एवं पारेषण टैरिफ) विनियमावली, 2019 में संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं। अधिसूचना संख्या यूपीईआरसी/प्रतिभूति/नियमन/2020-082/दिनांक 05 जून, 2020, अर्थात्:

1-संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ-

1.1 यह विनियमावली उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय वितरण एवं पारेषण टैरिफ) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2020 कहलायेगी।

1.2 यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

2-उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय वितरण एवं पारेषण टैरिफ) विनियमावली, 2019 के विनियम 16 "विद्युत क्रय लागत में हुई वृद्धि का उपचार" के प्रावधानों में संशोधन नीचे दिये गये हैं-

विनियमन 16 ईंधन अधिभार-

16.1 ईंधन अधिभार की वसूली-

(क) आयोग के अनुमोदन के बाद, वितरण अनुज्ञापिधारी तिमाही आधार पर जैसा कि नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है, परिवर्तनशील प्रभारों में भिन्नता के कारण हुए ईंधन अधिभार की वसूली करेगा।

(ख) ईंधन अधिभार की गणना एवं इसको भारित उन विद्युत स्रोतों की वास्तविक परिवर्तनशील लागतों में भिन्नता के आधार पर किया जायेगा जिनका टू-पार्ट टैरिफ है तथा जिनका ऊर्जा का स्रोत ईंधन हो, साथ ही साथ यह सम्बन्धित टैरिफ आदेश में अनुमोदित किया गया हो। शेष बची हुई वास्तविक विद्युत क्रय टू-अप में व्यवहृत की जायेगी।

(ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी को सभी उपभोक्ताओं से n^{th} तिमाही के लिए वसूले जाने वाले ईंधन अधिभार तथा हुई लागत का ब्योरा $(n+1)^{\text{th}}$ तिमाही के द्वितीय माह के प्रथम सप्ताह में विस्तृत गणना एवं सहायक अभिलेखों के साथ जैसा कि सत्यापन एवं अनुमोदन के लिए आयोग द्वारा वांछित हो, प्रस्तुत करेगा। $(n+1)^{\text{th}}$ तिमाही के दूसरे महीने के अन्तिम सप्ताह में एक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया आयोजित की जायेगी।

आयोग $(n+1)^{\text{th}}$ तिमाही के तीसरे महीने के दूसरे सप्ताह के अंत तक अनुमोदित करेगा। इसे $(n+1)^{\text{th}}$ तिमाही के तीसरे महीने के बिलिंग डेटा का प्रयोग करते हुए केवल $(n+2)^{\text{th}}$ तिमाही के प्रथम महीने से भारित एवं प्रभारित किया जायेगा। अनुमोदित ईंधन अधिभार की वसूली $(n+2)^{\text{th}}$ तिमाही के सभी तीन महीनों में की जायेगी।

इस प्रक्रिया की समय सीमा निम्नलिखित होगी—

गतिविधि	समय सीमा
फ्यूल सरचार्ज (FS) की फाइलिंग	फ्यूल अधिभार n^{th} तिमाही के तीन महीने के लिए, लाइसेंसधारी निर्धारित तरीके से $(n+1)^{\text{th}}$ तिमाही के दूसरे महीने के पहले सप्ताह में फाइल करेगा।
सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया	$(n+1)^{\text{th}}$ तिमाही के दूसरे महीने का अंतिम सप्ताह।
आयोग का आदेश	$(n+1)^{\text{th}}$ तिमाही के दूसरे सप्ताह।
फ्यूल सरचार्ज की वसूली	फ्यूल सरचार्ज $(n+2)^{\text{th}}$ तिमाही के सभी 03 महीनों में वसूल किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी $(n+2)^{\text{th}}$ तिमाही के प्रथम माह और उसके बाद के महीनों में फ्यूल सरचार्ज को बिल में भारित करने के लिए $(n+1)^{\text{th}}$ तिमाही के तीसरे महीने के बिलिंग डेटा का उपयोग करेगा।

16.2 ईंधन अधिभार की गणना के लिए सूत्र—

तिमाही के लिए ईंधन अधिभार नीचे दिये गये सूत्र के आधार पर निर्धारित किया जायेगा—

$$(FS)_n = [\{ \sum (VC)_i + (Excess \text{ or } Shortfall) \} / \sum (Q)_i] \times 10$$

जहाँ—

$(FS)_n$ Rs / kWh में है।

$(VC)_i$ = करोड़ रुपये में परिवर्तनीय लागत में भिन्नता है, n^{th} तिमाही के i^{th} माह में टू-पार्ट टैरिफ वाले विद्युत स्रोतों और जिनमें ऊर्जा के स्रोत के रूप में ईंधन होता है। यह ऐसे स्रोतों की कुल वास्तविक स्वीकार्य परिवर्तनीय लागत और आयोग द्वारा ऐसे स्रोतों की कुल स्वीकृत परिवर्तनीय लागत के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जायेगा।

$i = 1, 2$ और 3 n^{th} तिमाही के तीन महीने हैं

(Q)_i = nth तिमाही के ith महीने की MUs में वास्तविक बिक्री की मात्रा है,

(Excess of shortfall) फ्यूल सरचार्ज में आधिक्य या कमी है जो पिछली तिमाही (यों) में वसूल किया गया है, यदि कोई हो।

16.3 परिवर्तनशील अधिभारों में भिन्नता की गणना—

तिमाही के प्रत्येक महीने के लिए ईंधन अधिभार निम्नलिखित सूत्र के आधार पर निर्धारित किया जायेगा—

$$(VC)_i = (\text{Power Purchase Cost})_{\text{actual allowable}} - (\text{Power Purchase Cost})_{\text{approved}}$$

जहाँ—

$$(i) (\text{Power Purchase Cost})_{\text{approved}} = (\text{Per Unit Variable Cost})_{\text{approved}} \times (\text{Power Purchase Quantum})_{\text{approved}}$$

आयोग द्वारा अनुमोदित कुल बिजली खरीद के क्वांटम में ऊर्जा के स्रोत के रूप में ईंधन का प्रयोग करने वाले एवं टू-पार्ट टैरिफ विद्युत स्रोतों का हिस्सा लागू परिवर्तनीय लागत विद्युत खरीद स्रोत हैं।

जहाँ—

(Power Purchase Quantum)_{approved} एक महीने के लिए, संबंधित टैरिफ ऑर्डर में अनुमोदित सभी स्रोतों से खरीदी गई बिजली के मासिक क्वांटम पर उसी अनुपात को लागू करने से निर्धारित होगा, जैसा कि एक वर्ष के लिए सम्बन्धित टैरिफ आदेश में अनुमोदित सभी स्रोतों से क्रय की गयी कुल विद्युत खरीद की मात्रा एवं लागू परिवर्तनीय लागत वाले विद्युत क्रय स्रोतों से विद्युत की मात्रा का अनुपात हो।

(Per Unit Variable Cost)_{approved} का निर्धारण (Total Power Purchase Cost)_{approved} को (Total Power Purchase Quantum)_{approved} से विभाजित करके किया जायेगा।

जहाँ—

(Total Power Purchase Cost)_{approved} एक वर्ष के लिए संबंधित टैरिफ आदेश में अनुमोदित ऊर्जा के स्रोत के रूप में ईंधन का प्रयोग करने एवं टू-पार्ट टैरिफ वाले सभी विद्युत स्रोतों की लागू परिवर्तनीय लागत का योग है।

(Total Power Purchase Quantum)_{approved} एक वर्ष के लिए संबंधित टैरिफ आदेश में अनुमोदित ऊर्जा के स्रोत के रूप में ईंधन का प्रयोग करने एवं टू-पार्ट टैरिफ वाले सभी लागू विद्युत स्रोतों की विद्युत क्रय के क्वांटम का योग है।

$$(ii) (\text{Power Purchase Cost})_{\text{actual allowable}} = (\text{Per Unit Variable Cost})_{\text{actual allowable}} \times (\text{Power Purchase Quantum})_{\text{actual allowable}}$$

जहाँ—

किसी विशेष माह के लिए (Total Power Purchase Quantum)_{actual allowable} = Actual Retail Sales for the month (MUs) / [(1-Distribution Loss%) × (1-Intra State Transmission Loss%) × (1-Inter State Transmission Loss%)].

वास्तविक खुदरा बिक्री को उसी पद्धति के अनुसार ग्रास-अप किया जायेगा जैसा कि संबंधित टैरिफ आदेश में वितरण हानि, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन हानि और इंटर स्टेट ट्रांसमिशन हानि को ध्यान में रखते हुये (Total Power Purchase Quantum)_{actual allowable} को प्राप्त करने के लिए अनुमोदित है।

(Power Purchase Quantum)_{actual allowable} किसी विशेष महीने के लिए, की गणना (Total Power Purchase Quantum)_{actual allowable} से उसी अनुपात को लागू करने से होगी, जैसा कि एक वर्ष के लिए सम्बन्धित

टैरिफ आदेश में अनुमोदित सभी स्रोतों से क्रय की गयी कुल विद्युत खरीद की मात्रा एवं लागू परिवर्तनीय लागत वाले विद्युत क्रय स्रोतों से विद्युत की मात्रा का अनुपात हो।

$(\text{Power Purchase Cost})_{\text{actual allowable}}$ किसी विशेष माह के लिये एम०ओ०डी० को $(\text{Power Purchase Quantum})_{\text{actual allowable}}$ तक लागू करते हुए लागू परिवर्तनीय लागत विद्युत क्रय स्रोतों की वास्तविक परिवर्तनीय लागतों का योग होगी।

$(\text{Per Unit Variable Cost})_{\text{actual allowable}}$ किसी विशेष महीने के लिए $(\text{Power Purchase Cost})_{\text{actual allowable}}$ को उस विशेष महीने के लिए $(\text{Power Purchase Quantum})_{\text{actual allowable}}$ से विभाजित करके उसकी गणना की जायेगी।

16.4 भारत किया जाने वाला श्रेणी/उप-श्रेणीवार ईंधन अधिभार (n+2) तिमाही के प्रत्येक माह में निम्न सूत्र के आधार पर निर्धारित किया जायेगा—

(क) मीटर्ड खपत के लिए—[वर्ष के लिए टैरिफ आदेश में अनुमोदित उपश्रेणी उपभोक्ताओं का समेकित औसत बिलिंग दर $\text{ABR}(\text{in Rs./ kWh})/\text{वर्ष}$ के लिए टैरिफ आदेश में अनुमोदित वितरण अनुज्ञप्तिधारियों का समेकित सम्पूर्ण $\text{ABR}(\text{in Rs./kWh})] \times \text{ईंधन अधिभार (FS)}_n (\text{in Rs / kWh})$.

(ख) अन-मीटर्ड खपत के लिए—ईंधन अधिभार $(\text{FS})_n$ जैसे-जैसे उपश्रेणी उपभोक्ता के ए०बी०आर० में ईंधन अधिभार के कारण % वृद्धि/कमी एवं फिक्सड चार्जज में वृद्धि/कमी के अनुसार वसूल किया जायेगा, उदाहरणार्थ एक निश्चित उपश्रेणी के फिक्सड चार्ज X , ए०बी०आर० Y है तथा उपरोक्त आगणित ईंधन अधिभार Z है, उस दशा में ए०बी०आर० में % वृद्धि/ कमी $(Z / Y * 100)\%$ होगी तथा उपभोक्ता की इस उपश्रेणी से वसूला जाने वाला ईंधन अधिभार फिक्सड चार्ज में वृद्धि/कमी होगी, उदाहरणार्थ $X * (Z / Y)$.

16.5 अन्य प्रावधान—

- (क) उपश्रेणीवार ईंधन अधिभार संबंधित उपश्रेणी के। ABR के 10% (+) (-) पर सीमित होगा या किसी अन्य सीमा जैसा कि आयोग द्वारा निर्देशित किया जाये।
- (ख) ईंधन अधिभार की गणना दो डेसीमल तक की जायेगी।
- (ग) ईंधन अधिभार $(\text{FS})_n$ में किसी भी वृद्धि या कमी को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आगे ले जाया जायेगा और भविष्य में ऐसी अवधि में वसूल किया जायेगा जैसा कि आयोग द्वारा निर्देशित किया जाये।
- (घ) ईंधन अधिभार उपभोक्ता बिलों में एक अलग हेड के तहत दिखाया जायेगा। सकारात्मक ईंधन अधिभार के मामले में, ईंधन अधिभार हेड के तहत उपभोक्ताओं को अलग से कुल बिल में वृद्धि (+) दी जायेगी नकारात्मक ईंधन अधिभार के मामले में, ईंधन अधिभार हेड के तहत उपभोक्ताओं का अलग से कुल बिल में क्रेडिट (-) दिया जायेगा, ताकि प्रभावी रूप से आयोग द्वारा निर्धारित आधार टैरिफ वही रहे।
- (ङ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ईंधन अधिभार को नियमित तथा समय पर दाखिल किया जाना है, अन्यथा याचिका के प्रस्तुतीकरण के विलम्ब के लिए उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग (फीस एण्ड फाइन्स) विनियमावली, 2010 के प्रथम संवर्धन/संशोधन के क्रमांक 7, पार्ट-ए जनरल, फीस अनुसूची में संवर्धन, समय-समय पर संशोधित, में दिये गये अधिभार लागू होंगे।
- (च) आयोग, हालांकि, यदि वह इसे अधिक उपयुक्त मानता है, तो सूत्र/प्रक्रिया को उपयुक्त रूप से संशोधित/परिवर्तित कर सकता है।

आयोग के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग।

UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**No. U.P.E.R.C./Secy/Regulation/2020-082**

Lucknow dated : June 05, 2020

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred under Section 181 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) and all other powers enabling in this behalf, and after previous publication, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following Regulations to amend the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Multi Year Tariff for Distribution and Transmission) Regulations, 2019 *vide* Notification No. U.P.E.R.C./Secy/ Regulation/2020-082, dated June 05, 2020, namely :

1. Short Title and Commencement-

1.1 These Regulations may be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Multi Year Tariff for Distribution and Transmission), (First Amendment) Regulations, 2020.

1.2 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official *Gazette* of the Uttar Pradesh Government.

2. The provisions of Regulation 16 “Treatment of incremental Power Procurement Cost” of the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Multi Year Tariff for Distribution and Transmission) Regulations, 2019 are amended as hereunder:

Regulation 16. Fuel Surcharge–

16.1 Recovery of Fuel Surcharge-

(a) After the approval of the Commission, the Distribution Licensee shall recover the Fuel Surcharge incurred due to variation in variable charges, as detailed below, on a quarterly basis.

(b) The Fuel Surcharge shall be computed and charged on the basis of variation in actual variable cost of the power sources having two-part tariff and having fuel as a source of energy *vis-a-vis* the same approved in the concerned Tariff Order. All remaining actual power purchase shall be dealt in True-up.

(c) The Distribution Licensee shall submit details of the cost incurred and Fuel Surcharge to be charged to all consumers for the n^{th} quarter, along with the detailed computations and supporting documents as may be required for verification and approval of the Commission within 1st week of the second month of $(n+1)^{\text{th}}$ quarter. A public consultation process shall be held in the last week of the second month of $(n+1)^{\text{th}}$ quarter.

The Commission shall approve by the end of the 2nd week of the 3rd month of $(n+1)^{\text{th}}$ quarter. The same shall be levied and charged from the first month of $(n+2)^{\text{th}}$ quarter only using the billing data of 3rd month of $(n+1)^{\text{th}}$ quarter. The Fuel Surcharge approved, shall be levied in all 3 months of $(n+2)^{\text{th}}$ quarter.

The timelines for the process shall be as following :

Activity	Timelines
Filing of Fuel Surcharge (FS)	FS for the three months of n^{th} quarter, the Licensee will file in the 1 st week of 2 nd month of $(n+1)^{\text{th}}$ quarter in the prescribed manner
Public Consultation Process	Last week of 2 nd month of $(n+1)^{\text{th}}$ quarter
Order of Commission	2 nd week of 3 rd month of $(n+1)^{\text{th}}$ quarter
Levying of Fuel Surcharge	FS shall be levied in all 3 months of $(n+2)^{\text{th}}$ quarter. The Licensee will use the billing data of 3 rd month of $(n+1)^{\text{th}}$ quarter to charge FS in the bills of the 1 st month of $(n+2)^{\text{th}}$ quarter and so forth.

16.2 Formula for computation of Fuel Surcharge:

The Fuel Surcharge for the quarter will be determined based on the formula below:

$$(FS)_n = \{[\sum (VC)_i + (\text{Excess or Shortfall})] / \sum (Q)_i\} \times 10$$

Where:

$(FS)_n$ is in Rs. / kWh

$(VC)_i$ = is the variation in Variable Cost in Rs. Crore, of the power sources having two-part tariff and having fuel as a source of energy in i^{th} month of n^{th} quarter. This shall be determined as the difference between total actual allowable variable cost of such sources and the total approved Variable Cost of such sources by the Commission.

$i = 1, 2$ and 3 are the three months of the n^{th} quarter

$(Q)_i$ = is the quantum of actual sales in MUs of the i^{th} month of n^{th} quarter

(Excess or Shortfall) is excess or shortfall in Fuel Surcharge recovered in the previous quarter(s), if any.

16.3 Computation of variation in variable charges:

The Fuel Surcharge for each month of the quarter shall be determined based on the following formula:

$$(VC)_i = (\text{Power Purchase Cost})_{\text{actual allowable}} - (\text{Power Purchase Cost})_{\text{approved}}$$

Where:

$$(i) (\text{Power Purchase Cost})_{\text{approved}} = (\text{Per Unit Variable Cost})_{\text{approved}} \times (\text{Power Purchase quantum})_{\text{approved}}$$

The share of power sources having two-part tariff and having fuel as a source of energy in the total power purchase quantum approved by the Commission are the applicable variable cost power purchase sources.

Where:

(Power Purchase Quantum)_{approved} for a month, is determined by applying the same proportion on the monthly quantum of power purchased from all the sources approved in the concerned Tariff Order, as to the proportion of quantum of power from the applicable variable cost power purchase sources and the total quantum of power purchase from all the sources approved in the concerned Tariff Order for a year.

(Per Unit Variable Cost)_{approved} is determined by dividing the **(Total Power Purchase Cost)**_{approved} with the **(Total Power Purchase Quantum)**_{approved}.

Where:

(Total Power Purchase Cost)_{approved} is total of applicable variable cost of all the power sources having two-part tariff and having fuel as a source of energy as approved in the concerned Tariff Order for a year.

(Total Power Purchase Quantum)_{approved} is total of quantum of power purchase of all the applicable power sources having two-part tariff and having fuel as a source of energy as approved in the concerned Tariff Order for a year.

(ii) **(Power Purchase Cost)**_{actual allowable} = **(Per Unit Variable Cost)**_{actual allowable} × **(Power Purchase quantum)**_{actual allowable}.

Where:

(Total Power Purchase quantum)_{actual allowable} for a particular month = **Actual Retail Sales for the month (MUs) / [(1-Distribution Loss%) × (1-Intra State Transmission Loss%) × (1- Inter State Transmission Loss %)]**.

The Actual Retail Sales will be grossed up as per the same methodology as approved in concerned Tariff Order taking into consideration the approved Distribution Loss, Intra State Transmission Loss and Inter State Transmission Loss to find the **(Total Power Purchase Quantum)**_{actual allowable}.

(Power Purchase Quantum)_{actual allowable} for a particular month will then be calculated from the **(Total Power Purchase Quantum)**_{actual allowable} by applying the same proportion as to the proportion of quantum of power from the applicable variable cost power purchase sources and the total quantum of power purchase from all the sources approved in the concerned Tariff Order for a year.

(Power Purchase Cost)_{actual allowable} for a particular month will be total of actual variable costs of all the applicable variable cost power purchase sources by applying MOD upto the **(Power Purchase Quantum)**_{actual allowable}.

(Per Unit Variable Cost)_{actual allowable} for a particular month will be calculated by dividing the **(Power Purchase Cost)**_{actual allowable} for a particular month with the **(Power Purchase Quantum)**_{actual allowable} for that particular month.

16.4 Category / Sub- Category-wise Fuel Surcharge to be charged in each month of (n+2) quarter shall be determined based on the formula below:

a. For metered consumption:

[Consolidated Average Billing Rate (ABR) of Consumer Sub-category (in Rs. / kWh) as approved in the concerned Tariff Order/Consolidated Overall ABR of Distribution Licensee (in Rs. / kWh) as approved in Tariff Order for the year] x Fuel Surcharge (FS)_n (in Rs. / kWh).

b. For un-metered consumption:

The Fuel Surcharge (FS)_n shall be levied as the % increase/decrease in Fixed Charges *via-s-via* % increase/decrease in the ABR of Consumer Sub-category due to Fuel Surcharge *i.e.* say for a certain Sub-category the Fixed Charges is X, ABR is Y and the above computed Fuel Surcharge is Z, then % increase/decrease in ABR would be (Z/Y*100)% and the Fuel Surcharge to be charged from the consumer of this Sub-category will be as addition/reduction in Fixed Charges *i.e.* X * (Z/Y).

16.5 Other Provisions:

- a. The Sub-category-wise Fuel Surcharge shall be capped at (+) (-) 10% of the ABR of the respective sub-category, or any other ceiling as may be directed by the Commission.
- b. The computation of Fuel Surcharge will be done upto two decimals.
- c. Any excess or shortfall in the Fuel Surcharge (FS)_n shall be carried forward by the Distribution Licensee and shall be recovered over such future period as may be directed by the Commission.
- d. The Fuel Surcharge shall be shown under a separate head in the consumer bills. In case of positive Fuel Surcharge, the addition (+) to total bill shall be given to the consumers under the Fuel Surcharge head separately & in case of negative Fuel Surcharge, the credit (-) in total bill shall be given to the consumers under the Fuel Surcharge head, so that the base tariff determined by the Commission effectively will remain the same.
- e. Regular and timely filing of Fuel Surcharge has to be done by the Distribution Licensee, otherwise Surcharge for delay in submission of the Petition at Sl. no. 7, Part A General, Addendum to 'Schedule of Fees', in First Addendum/ Amendment to Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Fees & Fines) Regulation, 2010 as amended from time to time, will apply.
- f. The Commission may however, suitably modify / change the formula / procedure if it considers it to be more appropriate.

By the order of Commission,
SANJAY KUMAR SINGH,
Secretary,
Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission.